(घ) क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है, यदि हां, तो उक्त शिकायत के आधार पर कितने अधिकारियों को दोषी पाया गया है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० नयमेगौड़ा) : (क) से (ग) कोयला मंत्रालय भावी वितरण के लिए अर्द्ध-वार्षिक आधार पर राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को साफ्ट कोक का आवंटन करता है । कोल इंडिया लि० की सहायक कंपनियां राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा जारी प्रयोजनों के अनुसार भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर साफ्ट कोक का आपूर्ति करती है । राज्य-सरकारें/संघशासित क्षेत्र अपने क्षेत्राधिकार में साफ्ट कोक को फुटकर कीमतें निर्धारित करते हैं ।

(घ) कोयला मंत्रालय को राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों द्वारा निर्धारित कीमतों से अधिकतर फुटकर उपभोक्ताओं से कीमत लेने के संबंध में किसी शिकायत की जानकारी नहीं है । ऐसी शिकायतों की सुनवाई सम्बद्ध राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा की जाती हैं ।

Supply of coal to Raichur Thermal Power Station

1640. SHRI H. HANUMANTHAPPA: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether Government are aware that coal supply to Raichur Thermal Power Station in Karnataka is inadequate thereby hampering the power generation;

(b) whether any request has been made by the State Government in this regard; and

(c) if so, what steps Government propose to augment coal supply to this power station?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COAL (SHRI S. B. NYAMAGOUDA): (a) Yes, Sir. Raichur Thermal Power Station has received 1.031 million tonnes of coal from April to October' 91, against a linkage of 2.25 million tonnes, as per information received from Central Electricity Authority.

(b) Government of Karnataka have been requesting for increase in supply of coal to Raichur Thermal Power Station.

(c) The linkage of Raichur Thermal Power Station has been enhanced from 2.7 lakh tonnes in July-September' 91 to 3.15 lakh tonnes in October-December 91. The supply of coal to all thermal power stations, including Raichur, is being very closely monitored, and review meetings are taken every week in Cabinet Secretariat to monitor and regulate coal supplies to power sector.

सी० आई० एल० के अधीन वाशरीज का कार्य-चालन

1641. **श्री राम अवधेश सिंह** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा क्षेत्रवार कितनी कोल वाशरीज चलाई जा रही हैं ;

(ख) प्रत्येक वाशरी में एक वर्ष के दौरान मिडलिंग कोल और सलरी का कितनी मात्रा में उत्पादन होता है ; और

(ग) पिछले दस वर्षों के दौरान जिन ठेकेदारों ने सलरी और मिडलिंग कोल को उठाया है उनके नामों, उनको कुल आय और सरकार को अदा किए गए कर का ब्यौरा क्या है, क्या सलरी और मिडलिंग कोल को उठाने की व्यवस्था कतिपय व्यक्तियों के साथ स्थायी पट्टे के आधार पर की गई है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस०बी० नयमेगौड़ा) : (क) कोल इंडिया लि० की विभिन्न कोयला कंपनियों के अंतर्गत 15 वाशरी हैं । इस संबंध में ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

कोयला कंपनी	वाशरियों की संख्या	वार्षिक कार्यक्षमता (मि०टन) में)
(1) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड धनबाद	9	12.55
(2) सेंट्रल कोल-फील्ड लि०	5	11.47
(3) वैस्टनकोल-फील्ड्स लि० नागपुर	1	1.20
जोड़ :	15	25.22

(ख) और (ग) इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

रायल्टी की दरों में परिवर्तन करने से बिहार को हुआ घाटा

1642. **श्री राम अवधेश सिंह** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार 2 अगस्त 1991 से कोयले के संबंध में रायल्टी के परिवर्तन से पहले कोल इंडिया लिमिटेड से जो रायल्टी और सेस की धनराशि प्राप्त करता था अब उसे उससे कम धनराशि का राजस्व प्राप्त हो रहा है ;

(ख) "इस्को" और "टिस्को" द्वारा दी जा रही रायल्टी के कारण बिहार को राजस्व की कितनी धनराशि का नुकसान हो रहा है ; और

(ग) क्या भारत सरकार घाटे की तिपूर्ति करने का विचार रखती है, यदि हां, तो किस प्रकार से और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस०बी० नयमेगौड़ा) : (क) और (ख) 1-8-1991 से प्रभावी कोयले पर रायल्टी की संशोधित दरें बिहार सरकार द्वारा लगाया गया उपकर तथा रायल्टी की पहले की दोनों की दरों की तुलना में कम हैं । यह इसलिए हुआ क्योंकि बिहार राज्य ने कोयले पर उपकर ऊंची दरों पर लगा रखा था । रायल्टी की संशोधित दरें राज्यों के राजस्व की आवश्यकताओं तथा उपभोक्ताओं की हितों को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय आधार पर निर्धारित की गई हैं । अतः न्यायालय द्वारा उपकर को निरस्त कर दिए जाने के कारण राज्य सरकार के हुए घाटे की प्रतिपूर्ति किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(ख) इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही हैं और यथासंभव उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

इस्पात संयंत्रों को घटिया किस्म के कोयले की आपूर्ति

1643. **श्री राम जेठमलानी** :
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति कोल इंडिया लिमिटेड करता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अप्रैल 1991 से इन इस्पात संयंत्रों को भेजा जाने वाला कोयला घटिया किस्म का है ;

(ग) यदि हां, तो इस कोयले में राख की मात्रा कितने प्रतिशत होती है ;

(घ) क्या इस्पात क्षेत्र द्वारा इस संबंध में कोई शिकायत भी की गई है ; और